RAJ KUMAR MAURYA
Assistant Professor, Political Science
G.J. College, Rambagh, Bihta, Patna
B.A. I Year (H.) Paper - II
Political Science

विषय- रूस की संघीय परिषद (Federation Council of Russia)

संघीय परिषद रूस की संघीय सभा का उच्च सदन है, रूसी संघ का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो, वह इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है।

संघीय परिषद रूसी संघीय सभा का स्थायी निकाय है। संघीय परिषद की बैठक एक महीने में कम से कम दो बार होना आवश्यक है, इस सदन की ड्यूमा के साथ संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के भाषण, संवैधानिक न्यायालय के भाषण, विदेशी नेताओं के अभिभाषण के समय की जाती है।

इसकी गणपूर्ति कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्धारित होती है, कानून को स्वीकार करने के लिए इस सदन की

Scanned with CamScanner

साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के द्वारा वीटो किए गए किसी विधेयक को पुनः पारित करने के लिए तथा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 3/4 बहुमत की आवश्यकता संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिए होती है। 3/5 बहुमत की आवश्यकता संविधान सभा के गठन एवं ~~मौलिक~~ संविधान के मौलिक सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए आवश्यक होती है।

संघीय परिषद इसमा के सहयोग से कानूनों का निर्माण कार्य करती है। कानून निर्माण के लिए सर्वप्रथम कोई भी विधेयक को इसमा में पारित होता है। उसके पश्चात उस विधेयक को 5 दिनों के भीतर इसमा में भेजना अनिवार्य है। यदि किसी विधेयक को लेकर इसमा और संघीय परिषद के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक आयोग का गठन कर गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी इसमा इस आयोग

Scanned with CamScanner

इस आयोग की सिफारिशों पर सहमत न हो तो वह (ड्यूमा) मूल विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से ~~मूल~~ विधेयक को पारित कर सकता है।

संघीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव ड्यूमा को भेज सकती है।

राष्ट्रपति के चुनाव के सन्दर्भ में संघीय परिषद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, यह परिषद राष्ट्रपति पद के चुनाव की तिथि निर्धारित करती है। यद्यपि ड्यूमा के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है, ड्यूमा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर संघीय परिषद को भेजा जाता है, यदि यह सदन महाभियोग प्रस्ताव से सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, अगर यदि संघीय परिषद उस प्रस्ताव से असहमत है तो प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है।

रूस के संवैधानिक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं मध्यस्थता के उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उनके नाम की स्वीकृति संघीय परिषद से लेना आनिवार्य है।

राष्ट्रपति को मार्शल ला रूस में लागू करने के लिए संघीय परिषद से अनुमति लेना पड़ता है।

यदि रूस की किसी ईकाई की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो इसका अनुमोदन संघीय परिषद से लेना पड़ता है। यदि रूसी राष्ट्रपति अपातकाल घोषित करते है तो उसका भी अनुमोदन संघीय परिषद से लेना आनिवार्य है। यह सदन राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद में अपने 2 सदस्यों को भेजती है। यह रूसी सिविल सर्विस काउन्सिल में भी अपने अपने सदस्यों को नियुक्ती करती है,

विधायी क्षेत्र के सन्दर्भ में यदि हम संघीय परिषद से इयूमा की तुलना करें तो यह इयूमा की तुलना में कमजोर है।

Scanned with CamScanner